Problems have not been specified in the approved formula and distribution of Central assistance to the States is to be made in the light of plan discussion between Chief Ministers and the Deputy Chairman, Planning Commission.

Statement

Special Development Problems and weights suggested by the State Government of Reajasthan in their letter dated December 13, 1990

S. No	Problem	Weight(%)
1.	Desert	25
2.	Low Density	20
3.	Drought	15
4.	Small Plan	10*
5.	Environmental Issues	10
6.	Flood	5
7.	Urban Slums	5
8.	Coastal Area	5
9.	High Density of Population	5

*Based on gap between per capita outlay of the State and National Average.

2786. [*Transferred to the 26th March, 1992*]

2787. [*Transferred to the 27th March, 1992*]

Implementation of Women and Children's Programmes

2788. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has made any assessment of various programmes concerning women and children in rural areas;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Planning Commission has made any suggestion for new programmes for women and children in the Eighth Five year Plan; and

(d) what suggestions have been made by the Planning Commission to tone up the implementation of the existing women and children's programmes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Specific assessment of various programmes concerning women and children in rural areas has not been made by the Planning Commission. However, broad review of programmes for women and child development is a continuous process and is carried out through progress reports, reports of committees, Working Groups, workshops etc. For the formulation of the Eight Plan, Steering Groups/Working Groups were constituted to review the existing programmes and to make suggestions for the Eighth Plan. These reviews, while noting improvements in the status of women and children, have also indicated *inter alia* that coordination between various programmes implemented by different ministries needs to be strengthened, greater flexibility is necessary in the schemes so that they could be oriented according to local requirements, adequate supportive services need to be provided, community participation strengthened, special programmes developed for categories not adequately covered, and administrative arrangements strengthened. (c) and (d) The Eighth Plan is yet to be finalised. Improvement in implementation of programmes for women and children would require better integration, coordination and convergence of services, strengthening and consolidation of the inter linkages, strengthening of administrative arrangements, people's participation, training of manpower, decentralised planning and implementation, and monitoring of programmes at different levels.

मध्य प्रदेश में बस्तर क्षेत्र का विकास

2789. **श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों से उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बस्तर के आदिवासी एवं अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ अन्य योजनाएं बनाने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बस्तर क्षेत्र खनिजों और वन संसाधनों दोनों अर्थों में राज्य के अत्यधिक सम्पन्न क्षेत्रों में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए बस्तर में भी जारी है। खनिजों के मामले में लौह अयस्क, टीन, इत्यादि के निक्षेपों पर मुख्य बल दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश का बस्तर क्षेत्र मुख्यतः जनजाति क्षेत्र है। जनजाति उप योजना मध्य प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित की जा रही है। बस्तर जिले में जनजाति उप योजना सात समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजाति उप योजना की कार्यनीति प्रत्येक लाभग्राही को उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने, उनका जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सेवाओं के पैकेज प्रदान करने और उनको आय सृजन करने वाली स्कीमें प्रदान करने पर बल देती हैं, ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त, ऐसी आधार संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो उन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाने में समर्थ बना सकें। जन जाति उप योजना के तहत विकास की प्रेरणा, राज्य योजना से मिलती है। केन्द्र ने राज्य योजना प्रयासों को बढ़ावा देने के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। यद्यपि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, फिर भी, जनजाति उपयोजना के तहत स्कीमें जारी रखे जाने की संभावना है।

बिहार को सिंगरौली से बिजली दिया जाना

2790. **श्री राम अवधेश सिंह**: क्या योजना और **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि मध्य बिहार में सामूहिक नर-संहार वहां की आर्थिक बदहाली की वजह से होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जब तक वहां लघु उद्योगों का जाल बिछाकर भूमिहीन मजदूरों या सीमांत किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई जाती और ऐसा करके कृषि भूमि पर उनकी निर्भरता के दबाव को नहीं घटाया जाता तब तक उस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की जा सकती ; और

(ग) क्या सरकार सिंगरौली से बिहार को 5,000 मेगावाट बिजली देने के लिए राजी होगी ताकि बाहर से उद्योगपति वहां जाएं और उद्योग लगाएं क्योंकि अब लोहा, इस्पात तथा कोयले से रेल माल भाड़ा समानीकरण नीति समाप्त कर दी गई है, यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) राज्य में क्षेत्र का विकास, इस की योजना तथा निधियों के आवंटन की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की है। विभिन्न कारणों अर्थात् सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कारणों से मध्य बिहार में सामूहिक नर-संहार होता रहता है। मध्य बिहार में सामूहिक नर-संहार के लिये केवल आर्थिक पिछड़ापन ही जिम्मेदार नहीं हो सकता।

(ग) सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना (2,000 मेगावाट) एक केन्द्रीय क्षेत्र पावर परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रेदश में स्थित है। केन्द्रीय परियोजनाओं से बिजली के आवंटन के लिए विद्यमान साझा फार्मूला के अनुसार क्षेत्र के उन राज्यों के बीच बिजली का समान रूप से बटवारा किया जाता है जहां परियोजना स्थापित की जाती है। सामान्य तौर पर क्षेत्रीय परियोजनाओं से बिजली, क्षेत्र से बाहर के राज्यों के लिये निर्धारित नहीं की जाती। फिर भी, सामान्यतः एक दूसरे क्षेत्र से बिजली का आदान-प्रदान किया जाता है जो दिन प्रति दिन की मांग और सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करता है।

Targets fixed for Poverty Alleviation during Eighth Five Year Plan

2791. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the Government's stand on "alleviation of poverty";

(b) whether there is a proposal to merge all the poverty alleviation programmes in one major programme;

(c) what are the targets under different programmes during the Eighth Plan for alleviation of poverty; and

(d) what is the number of people below poverty line State-wise vis-a-vis per capita income of the people of these States?